समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का आरोप : अडानी को भागलपुर पावर प्लांट के लिए 1,050 एकड़ जमीन गिफ्ट मे दी गई

Publisher

Published on 15 Sep 2025

बिहार चुनाव 2025 के मद्देनज़र, कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि उद्योगपति गौतम अडानी को बिहार के भागलपुर में पावर प्लांट के लिए **1,050 एकड़ जमीन गिफ्ट मे दी गई है**। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम न केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग है, बल्कि उद्योगपति को अनावश्यक लाभ पहुंचाने वाला है।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इस पावर प्लांट के निर्माण और संचालन पर होने वाला खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं, अडानी ग्रुप को यह सुविधा दी जाएगी कि वे जनता को इस पावर प्लांट से महंगी बिजली बेच सकेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी योजना उद्योगपतियों और सत्ता पक्ष के लिए विशेष लाभ सुनिश्चित करने की नीतिगत चाल है।

बीजेपी सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि भूमि आवंटन नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार हुआ है। वहीं, अडानी ग्रुप का कहना है कि यह परियोजना देश के ऊर्जा क्षेत्र और बिहार में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रुप का दावा है कि इस पावर प्लांट से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

भागलपुर पावर प्लांट का मुद्दा बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। कांग्रेस का आरोप यह संकेत देता है कि बीजेपी सरकार बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में कार्य कर रही है। इससे चुनावी लड़ाई में विपक्ष को चुनावी मुद्दा मिल सकता है। वहीं, बीजेपी का यह कहना है कि यह परियोजना राज्य और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की परियोजनाएँ हमेशा विवादास्पद होती हैं। भूमि आवंटन और सरकारी खर्च पर होने वाले आरोप अक्सर चुनाव के समय जोर पकड़ते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सरकार और उद्योगपति पारदर्शी रूप से इस परियोजना की जानकारी साझा करते हैं, तो विवाद कम किया जा सकता है।

भागलपुर के स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पावर प्लांट क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। वहीं, कुछ लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि उद्योगपति को मिलने वाली सुविधाएँ और लाभ जनता के हित में नहीं होंगे। स्थानीय राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को चुनावी रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं।

भागलपुर पावर प्लांट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा न केवल चुनावी मुद्दा बन सकता है, बल्कि जनता के बीच राजनीतिक संदेश भी फैलाएगा। दोनों पक्ष अपनी रणनीति के तहत मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कांग्रेस का आरोप और बीजेपी का प्रतिपक्षी पक्ष यह दिखाता है कि भागलपुर पावर प्लांट राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। अडानी ग्रुप को भूमि देने का मुद्दा न केवल बिहार चुनाव की गर्मी बढ़ा सकता है, बल्कि उद्योगपति और सरकार के संबंधों पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। जनता के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस परियोजना का वास्तविक लाभ कहाँ तक पहुँचता है और क्या यह परियोजना पारदर्शिता और न्यायसंगत तरीके से संचालित होती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.